

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1905 / 2010 / जयपुर.
2. अपील संख्या - 1946 / 2010 / जयपुर.
3. अपील संख्या - 1947 / 2010 / जयपुर.
4. अपील संख्या - 1948 / 2010 / जयपुर.
5. अपील संख्या - 1428 / 2011 / जयपुर.

मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
एफ-549, रोड नं० 6, वी.के.आई. एरिया, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

6. अपील संख्या - 2121 / 2011 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
एफ-549, रोड नं० 6, वी.के.आई. एरिया, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. सी. अग्रवाल व

श्री एस. श्रीधरण, अभिभाषकगण

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/01/2016

निर्णय

1. अपील संख्या 1905 / 2010, 1946 / 2010, 1947 / 2010, 1948 / 2010 व 1428 / 2011 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 2121 / 2011 अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय/तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के पृथक-पृथक पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।





लगातार.....2

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधियों में 'सूजी टोस्ट' (RUSK) का कर मुक्त विक्रय किया है। अपीलार्थी ने RUSK की बिक्री अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 34 'Bread (branded or other wise excluding Pizza bread)' से आच्छादित मानते हुए करमुक्त की गयी। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की

आलौच्य अवधियों के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 24/25 के तहत पारित करते हुए उक्त करमुक्त बिक्रीत माल RUSK का वेट अधिनियम की किसी भी अनुसूची में इन्द्राज नहीं होने से इसे सामान्य दर से कर योग्य मानते हुए 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया। साथ ही अपील संख्या 1905/2010 कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित प्रकरण में क्लॉजिंग स्टॉक की बिक्री मानते हुए कर रुपये 54,108/- एवं ब्याज रुपये 11,363/- का भी आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से अस्वीकार की गई, किन्तु कर निर्धारण वर्ष 2009-10 (तृतीय व चतुर्थ तिमाही) से सम्बन्धित प्रकरण में धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील संख्या 2121/2011 प्रस्तुत की गयी है।

4. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक	अवधि	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
1905/10	12.07.2010	07.01.2010	2006-07	8,60,315 + 54,108	2,33,682 + 11,363	-
1946/10	03.09.2010	13.10.2009	2006-07	14,31,103	3,43,465	28,62,206
1947/10	03.09.2010	07.01.2010	2006-07	21,71,095	3,25,664	43,42,190
1948/10	03.09.2010	07.01.2010	2006-07 (I & II Qtr.)	14,54,727	1,01,831	29,09,454
1428/11 2121/11	18.05.2011	08.09.2010	2007-08 (III & IV Qtr.)	21,81,804	1,74,544	43,63,608

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि RUSK भी एक प्रकार का Bread ही है। Rusk व Bread में मशीनरी समान है, बनाने की प्रक्रिया समान है, प्रयुक्त सामग्री के घटक identical (समकक्ष) हैं। केवल excess moisture को remove किया जाता है। Rusk, Bread का ही रूप है, जिसमें घटक से लेकर निर्माण तक सब कुछ समान है, ऐसी स्थिति में

लगातार.....3

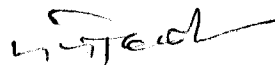
1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948 / 10 एवं 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर

Rusk भी करमुक्त विक्रय योग्य वस्तु है। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में दिये गये निर्णयों को नजरअंदाज करते हुए Rusk को सामान्य दर से करारोपण योग्य अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये हैं :-

- (1) अपीलीय अधिकरण दिल्ली के अपील संख्या 232/ATVAT/07-08/DUAT में पारित आदेश दिनांक 25.01.2008
- (2) Financial Commissioner Delhi Administration: Delhi द्वारा निगरानी संख्या 254/1972 मैसर्स आदर्श बेकरी बनाम दी स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 29.08.1972
- (3) आयुक्त, वाणिज्यिक कर कर्नाटक का कर्नाटक वैट एक्ट, 2003 की धारा 59(4) के तहत जारी अग्रिम स्पष्टीकरण
- (4) बिहार वैट एक्ट, उड़ीसा वैट एक्ट, पश्चिम बंगाल वैट एक्ट में किया गया RUSK का वर्गीकरण
- (5) माननीय केरल उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1993) 88 एस.टी. सी. 9 मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) बिक्री कर विशेष वृत्त
- (6) माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1976) 2 एस.सी.सी. 2441 डनलप इण्डिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया

6. अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित वस्तु RUSK को करयोग्य ठहराने के भार का निवर्हन नहीं किया है, जो कि कर निर्धारण अधिकारी का प्रथम दायित्व था। तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :-

- (7) माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2005) 2 एस.सी.सी. 669 (एस.सी.) स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा बनाम ब्रेडमा इण्डिया लिमिटेड
- (8) माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1953) 4 एस. टी.सी. 387 (हैदराबाद) कायानी एण्ड कम्पनी बनाम सी.एस.टी.
- (9) माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1990) 45 ई.एल.टी. 528 (एस.सी.) भारत फोर्ज एण्ड प्रेस इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज



लगातार.....4



1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948 / 10 एवं 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर.

7. वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत समस्त माल का इन्द्राज उसकी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ है, ऐसी स्थिति में शास्ति का आरोपण अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का समुचित अवलोकन किये बिना धारा 61 की शास्ति की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की है। तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये :-

(10) माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य

(11) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड श्रीगंगानगर

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त न्यायिक दृष्टान्तों तथा चैम्बर्स, ऑक्सफोर्ड व वेबस्टर्स डिक्शनरीज में दी गयी RUSK की परिभाषा का हवाला देते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत RUSK वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 34 में ही सम्मिलित होगा। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

11. हस्तगत प्रकरण में दो विवादित बिन्दु निम्न प्रकार हैं :-

(अ). अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल RUSK Bread अनुसूची-I की प्रविष्टि 34. 'Bread (branded or other wise) excluding Pizza bread.' में शुमार है अथवा नहीं, तथा करमुक्त है अथवा कर योग्य ?

(ब). अपीलार्थी व्यवहारी के अंतिम स्टॉक पर करारोपण किया गया, जो विधिसम्मत है अथवा नहीं ?





लगातार.....5

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

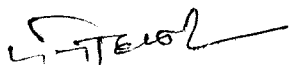
12. प्रथम बिन्दु के निस्तारण हेतु वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 34 एवं सम्बद्ध प्रावधानों का अवलोकन समीचीन है, जो निम्न प्रकार हैं :-

34. 'Bread (branded or other wise) excluding Pizza bread'

13. वेट अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रकार है :-

4. Levy of tax and its rate. -

- (1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules.
- (2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which no tax under sub-section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub-section (1) of section 18, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule-III to Schedule VI of the Act.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax payable by the dealer covered by sub-section (2) of section 3, shall be levied at the rate not exceeding two percent on the turnover, as may be notified by the State Government.
- (4) Where any goods are sold packed in some material, whether charged for separately or not, notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax liability of and the rate of tax on the packing material shall be according to the tax liability of and the rate of tax on the goods packed therein.
- (5) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedules, prospectively or retrospectively, or reduce the rate of tax payable in respect of any goods and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.





लगातार.....6

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948 / 10 एवं 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर.

- (6) Every notification issued under sub-section (5) shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for period of not less than thirty days which may comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.
- (7) Notwithstanding anything contained in this Act, any registered dealer, who imports into, or manufactures in, the State such goods as may be notified by the State Government, may, at his option, pay, in lieu of the tax payable by him on sale price of such goods under this Act, a tax at full rate on the maximum retail price of such goods in the manner as may be prescribed:

Provided that where a dealer has purchased any goods -

- (a) from aforesaid importer or manufacturer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods; or
- (b) from another registered dealer where tax on the maximum retail price of such goods was paid in the State on an earlier occasion,

the purchasing dealer, irrespective of whether he is registered or not, while making resale of such goods in the State, shall, notwithstanding anything contained elsewhere in the Act, be entitled to recover from the buyer the amount of tax paid by him at the time of purchase of such goods under such conditions and restrictions, and in such manner, and within such time, as may be prescribed.

14. वेट अधिनियम की धारा 8 निम्न प्रकार है :-

8. Exemption of tax. -

- (1) The goods specified in the Schedule-I shall be exempt from tax, subject to such conditions as may be specified therein.
- (2) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-I, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.



लगातार.....7

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

(3) The State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may exempt whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase by any person or class of persons as mentioned in Schedule-II, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.

(3A) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-II, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(4) The State Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, notify grant of exemption from payment of whole of tax payable under this Act in respect of any class of sales or purchases for the purpose of promoting the scheme of Special Economic Zones or promoting exports, subject to such conditions as may be laid down in the notification.

(5) Every notification issued under this section shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than thirty days, which may comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

15. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में निम्नानुसार विधिक व्याख्या एवं व्यवस्था दी गयी है :-

(a) अपीलीय अधिकरण दिल्ली के अपील संख्या 232/ATVAT/07-08/DUAT में पारित आदेश दिनांक 25.01.2008 :-

".....Whether 'Rusk' is covered under entry no. 34 of the First Schedule of DVAT Act i.e. 'Bread' and is an exempted commodity?"



लगातार.....8

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

.....that since Bread is an exempted commodity and when the ingredients of the Rusk and Bread are the same and the manufacturing process is also the same except that the Rusk is baked twice then there is no reason as why the Rusk be also not covered under entry No.34 of the First Schedule of the Act, the exempted commodity and so far as the ingredients of the 2 items, i.e., Bread and Rusk are concerned, we have taken through Page 9 of the appeal, which contains the ingredients of the Bread and Rusk as under :-

INGREDIENTS OF BREAD & RUSK

BREAD	RUSK
Maida	Maida
	Suzi
Yeast	Yeast
Edible Oil / Vanaspati Ghee	Edible Oil / Vanaspati Ghee
Salt	Salt
Sugar	Sugar
Soya Flour	Soya Flour
Improvers	Improvers
Preservatives	Preservatives
	Saunf
	Elaichi
Water	Water

.....However, his main plant of argument is, that earlier too as long back as on 29/08/1972, the then Financial Commissioner, Delhi Government i.e. the Predecessor Court, in an exactly similar case entitled Adarsh Bakery Vs. The State, had the occasion to determine the matter and the Ld. Financial Commissioner vide Order No. 254 of 1972 dated 29/08/1972 had held conclusively that "Rusks" would fall within the connotation of the term "Bread" and would be exempted from the levy of tax."

(b) **Financial Commissioner Delhi Administration: Delhi - निगरानी संख्या 254/1972 मैसर्स आदर्श बेकरी बनाम दी स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 29.08.1972 :-**

HELD : that 'Bread' as used in item No. 3 of the Second Schedule includes all preparations from flour, sugar and salt moistened kneaded and baked as in the case of Bread (Double Roti) and Buns and since Rusks though called by a different nomenclature are also prepared as per the said process and from the said specified ingredients, these would also fall within the connotation of the term 'bread' & would be exempted from the lavy of Sales Tax being an item included in the 2nd Schedule."





लगातार.....9

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948 / 10 एवं 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर.

- (c) आयुक्त, वाणिज्यिक कर कर्नाटक का अग्रिम स्पष्टीकरण धारा 59(4) कर्नाटक वैट एक्ट, 2003 :-

"In their application cited above, the petitioner-dealer has sought clarification regarding the rate of VAT on Bakery/ Confectionery products such as: Bread, Buns, Pav, Bread Stick, Bread Rolls, Pizza Base, Bread Crumb, Bread Rusk etc.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and the collection of revenue. it is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provisions and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR CR 263/05-06 DATED : 28-03-2006

It is hereby clarified that rates of tax on Bakery/Confectionery products are as follows.

Bread Buns, Pav, Bread Stick, Bread Rolls, Bread Crumb, Bread Rusk	These products are exempt from tax as per entry No. 12 of First Schedule under Karnataka Value Added Tax Act, 2003.
Pizza Base	This product is not enumerated in any of the Schedules/Notifications and is therefore taxable at 12.5% under Section 4(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

- (d) बिहार वैट एक्ट, उड़ीसा वैट एक्ट, पश्चिम बंगाल वैट एक्ट में RUSK को Hardened Bread घोषित किया गया है।
- (e) माननीय केरल उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1993) 88 एस.टी. सी. 9 :-

"8. The material averments regarding the composition and components of the product, manufacturing process involved, and the sale pattern employed, uncontradicted by any counter-affidavit as matters now stand, may be summarized as follows :

9. The material averments, according to the petitioners, are :

"Bun is really Bread in a different shape. The ingredients or raw materials of Bread and bun are the same, the process of manufacture is the same, and the commercial identity is the same. Bread itself is manufactured and marketed in different shapes with

लगातार.....10

differing qualities, as loaves, rolls, brown bread, sweet bread etc. The ingredients of bread and bun are same, viz., maida, sugar, salt, fat, yeast, GMS, vitamins, premix, potassium bromate, acetic acid and calcium propionate. The process of manufacture is also identical. In the case of both bun and bread the various steps and stages in manufacture are mixing raw materials fermenting, remixing, dividing, rounding and moulding, pruning, baking, cooling and packing."

"The ingredients of bread and bun are maida, sugar, salt, fat, yeast, glycerine mono stala, vitamin premix, potassium bromate, acetic acid and calcium propionate. The manufacturing process is also the same. The flour is sifted and the raw materials are mixed with water to form a dough. It is then fermented and remixed. The remixed dough is allowed a short resting period before it is divided to form each bread or bun. It is then rounded, moulded, panned, pruned to the required volume and baked. The baked bread is cooled to room temperature and sliced and packed. The cooled bun is directly packed without slicing. In bur the percentage of yeast is more than bread."

- (f) माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1976) 2 एस.सी.सी. 2441 डनलप इण्डिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :-

"35. When an article has, by all standards, a reasonable claim to be classified under an enumerated item in the Tariff Schedule, it will be against the very principle of classification to deny it the parentage and consign it to an orphanage of the residuary clause. The question of competition between two rival classifications will, however, stand on a different footing.

36. It is not for the Court to determine for itself under Article 136 of the Consitution under which item a particular article falls. It is best left to the authorities entrusted with the subject. But where the very basis of the reasons for including the article under a residuary head in order to charge higher duty is foreign to a proper determination of this kind this Court will be loath to say that it will not interfere."

16. यह निर्विवादित है कि Bread Rusk का 'सूजी टोस्ट' ब्रांड नाम है। RUSK का भी उन्हीं ingredients से विनिर्माण किया जाता है, जिनसे कि Bread का विनिर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त RUSK में सूजी, सौंफ, इलायची भी थोड़ी मात्रा में मिश्रित होता है। सिवाय इसके कि RUSK को दो बार bake किया जाता है।





1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

17. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I की प्रविष्टि-34 में Bread को करमुक्त घोषित किया गया है।

18. बिहार वैट अधिनियम, 2005 के तहत जारी अनुसूची-III (कर दर 5%) के पार्ट-I की प्रविष्टि संख्या 107 निम्न प्रकार है :-

"Rusk that is hardened bread."

19. वेस्ट बंगाल वैट एक्ट, 2005 की अनुसूची-सी पार्ट-I प्रविष्टि संख्या 67 निम्न प्रकार है :-

"Rusk that is hardened bread."

20. इसी प्रकार माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

(a) माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2014) 73 वी.एस.टी. 257 (एम.पी.) बाल गोविन्द अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य :-

"9. The question that falls for consideration is whether the State Government could have issued the notification excluding 'dried singhada'. It is worth noting here that section 9 of the Act relates to levy of tax. It provides that the tax shall be levied on the taxable turnover relating to goods specified in Schedule II. In Part V of the Schedule II it has been mentioned that "'kirana" goods, as the State Government may by notification specify'. Submission of Mr. Kumares Pathak, learned counsel for the State, is that 'singhada' has been notified in the list of 'kirana' goods of Schedule II. In Schedule I 'singhada' has been treated as a tax -free goods. Section 15(2) confers power on the State Government to amend Schedule I. The said power is a restricted and constricted one. To elaborate, it only confers power for inclusion or adding certain qualifiers. In Ruchi Fabrics Ltd. v. State of M.P. : [2000] 117 STC 273 (SC) a two Judge Bench of the apex court while dealing with section 10(2) of the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 and the issuance of notification under section 21 of the M.P. General Clauses Act, 1957 by which certain items were excluded expressed the view as under:

'By virtue of section 10(2) of the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958, the State Government is given power, by notification to amend Schedule I only "so as to include therein goods not already specified or relax or omit any of the conditions and exceptions set out in the corresponding entry in the third column thereof. The Legislature, therefore, empowered the State Government

लगातार.....12

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

to amend Schedule I only to the extent of widening the scope thereof either by including therein goods which had not already got its benefit or by relaxing or removing conditions which were a pre-requisite for obtaining the exemptions thereunder. No power was conferred by the statute upon the State Government in any way to curtail the scope of Schedule I. Therefore, notification dated September 20, 1990 by which certain varieties of cloth that were covered by the First Schedule as it originally stood were excluded, is ultra vires the powers of the State Government under section 10(2).'

10. In the said case their Lordships expressed the opinion that Schedule I is a part of the original statute and it is a creation of the Legislature. In view of the aforesaid pronouncement, the State Government could not have excluded any item by issue of a notification. Serial No. 16 of Schedule I uses the terms 'singhada'. The intention of the Legislature, as is manifest, is to include dried 'singhada'. It is noticeable wherever Legislature wanted exclusion of dried item has specifically mentioned the same and this is evincible from the words used 'excluding dried ginger in entry No. 16. The same is not the tenor in case of 'dried singhada'. Had the Legislature intended only to except green (fresh) alone 'singhada' that would have been clearly indicated. In the absence of such exclusion, we are of the considered opinion that the notification issued by the State Government travels beyond the statutory limits. The clarificatory circulars, in our considered opinion, is totally inconsequential. Therefore, we conclude and hold that, as long as, section 15(2) remains in force and Schedule I being the creation of Legislature, its effect cannot be nullified and its scope cannot be curtailed by issuance of a notification."


- (b) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2015) 77 वी. एस.टी. 209 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, जयपुर बनाम डेज मेडिकल स्टोर लिमिटेड :-

"The burden to prove that a certain items is exigible to tax and falls under a given taxable entry is always on the Revenue."

- (c) माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2011) 46 वी. एस.टी. 79 (एम.पी.) केडिला हेल्थ केयर लिमिटेड व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर व अन्य :-

"The following are the well-settled principles regarding interpretation of taxing statues-

- (i) A taxing statute has to be strictly construed. The subject is not to be taxed without clear words for that purpose.





लगातार.....13

1-6. अपील संख्या-1905, 1946, 1947, 1948/10 एवं 1428 व 2121/2011/जयपुर.

(ii) The provisions of the Act must be read according to natural construction of its words.

(iii) No tax can be imposed by inference or by analogy or by trying to probe into the intention of the Legislature.

(iv) Before taxing any person, it must be shown that he falls within the ambit of charging section by clear words used in the section.

(v) If certain words are used in the statute which are capable of being construed in a popular sense, their common parlance meaning has to be taken into account.

(d) माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1953) 4 एस. टी.सी. 387 :-

Exemption 'Bread' meaning of whether include All kinds of Bread.

In our view, 'bread' includes and should include all forms or kinds of bread which are prepared by moistening, kneading, baking, frying or roasting meal or flour with or without the addition of yeast, leaven or any other substance for puffing or lightening the article.

(e) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2011) 46 वी.एस. टी. 297 (मद्रास) :-

".....The term 'otherwise' means dealing with the materials purchased in any other manner too."

21. 'RUSK' वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 34 से करमुक्त घोषित है। अनुसूची-I, मूल अधिनियम/संविधि का भाग है। विधायिका ने Bread को करमुक्त घोषित किया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित निर्णय (2014) 73 वी.एस.टी. 257 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अनुसूची-I में घोषित करमुक्त वस्तु में शुमार होने वाली वस्तु पर करारोपण नहीं किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टान्त (1953) 4 एस.टी.सी. 387 के प्रकाश में Bread से आशय समस्त प्रकार की Bread से है। कर निर्धारण अधिकारी ने करारोपण करते समय सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया है कि RUSK वेट अधिनियम की किस अनुसूची की प्रविष्टि में कर योग्य है ?

22. उपरोक्त विस्तृत विवेचना, न्यायिक दृष्टान्त, (दिल्ली अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय), आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक का अग्रिम स्पष्टीकरण एवं बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के वेट अधिनियमों के तहत दी गयी Rusk की परिभाषा के मद्देनजर यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल "RUSK" राज्य सरकार द्वारा अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या





लगातार.....14

1-6. अपील संख्या—1905, 1946, 1947, 1948 / 10 एवं 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर.

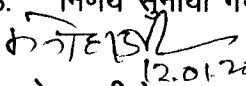
34 में कर मुक्त घोषित प्रविष्टि 'Bread (branded or other wise) excluding Pizza bread' में शुमार होता है, अतः करमुक्त है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Rusk पर सामान्य दर से कर, तदनुसार ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आरोपण की पुष्टि किये जाने में विधिक भूल की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

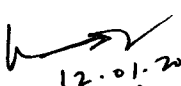
23. अपील संख्या 1905 / 2010 कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के क्लॉजिंग स्टॉक पर कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। यह निर्विवादित है कि किसी भी वस्तु पर कर का आरोपण तभी हो सकता है, जब कर निर्धारण अधिकारी उक्त वस्तु की बिक्री को प्रमाणित करे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उक्त दायित्व का निर्वहन करने में पूर्णतया सफल रहे हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपने क्लॉजिंग स्टॉक का विक्रय किया गया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2006) 15 टैक्स अपडेट 241 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड-तृतीय, वृत्त-एच, जयपुर बनाम मैसर्स ईलाइट जैम हाऊस, रामगंज बाजार, जयपुर एवं (2003) 2 आर.टी.आर. 76 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, राजसमन्द बनाम मैसर्स मार्ब्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., पसून्द (राजसमन्द) में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यवहारी के क्लॉजिंग स्टॉक पर करारोपण नहीं किया जा सकता। अतः इस बिन्दु पर भी कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

24. जहां तक अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2121 / 2011 का प्रश्न है, समस्त प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को ही अपास्त किया जा चुका है तो करापवंचन हेतु वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति का आरोपण स्वतः अपास्तनीय है। अतः इस सीमा तक अपीलीय आदेश दिनांक 08.09.2010 की पुष्टि करते हुए, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

25. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी पाँचों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2121 / 2011 अस्वीकार की जाती है।

26. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य